

सफलता: 87 करोड़ बैंक खातों को आधार नंबर से जोड़ा

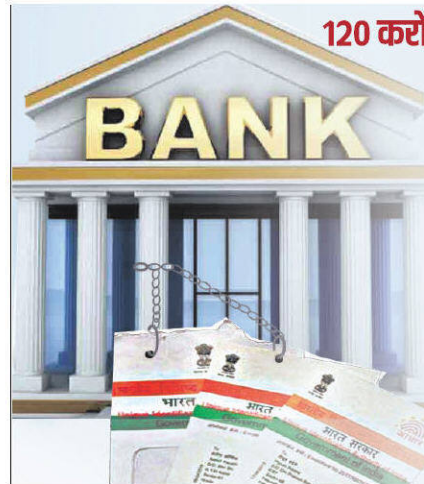
नई दिल्ली | एजेसी

देश भर में 80 प्रतिशत बैंक खातों और 60 प्रतिशत मोबाइल नंबर को आधार से जोड़ा जा चुका है। आधार योजना का प्रबंधन करने वाली एजेसी यूआईडीएआई के एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि समयसीमा खत्म होने के एक माह पहले 109.9 करोड़ खातों में से लगभग 87 करोड़ को आधार से जोड़ दिया गया है। साथ ही इनमें से 58 करोड़ बैंक खातों का सत्यापन हो चुका है। जबकि बाकी में बैंक में दारखल दस्तावेजों के साथ सत्यापन प्रक्रिया जारी है। सरकार ने

इस काम के लिए 31 मार्च 2018 तक का समय रखा है।

पैन कार्ड और मोबाइल सिम भी शामिल : केंद्र सरकार को उम्मीद है इस पहल से अघोषित धन-संपत्ति पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। इसी उद्देश्य से पैन संख्या को भी आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है। सभी मोबाइल सिम 31 मार्च तक आधार से जोड़े जाने हैं ताकि मोबाइल फोनधारकों की पहचान सुनिश्चित हो। अधिकारी ने कहा कि 142.9 करोड़ सक्रिय मोबाइल कनेक्शनों में से 85.7 करोड़ को पहले ही आधार से जोड़ा जा चुका है। शेष को मार्च तक जोड़ लिए जाने की उम्मीद है।



120 करोड़ से अधिक के पास आईडी

यूआईडीएआई के सीईओ अजय भूषण पांडे ने बताया कि 120 करोड़ से अधिक नागरिकों को आधार आईजी जारी हो चुकी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि 31 मार्च तक 100 फीसदी आधार सत्यापन पूरा हो जाएगा। ज्यादातर सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाएं आधार को निवास पहचान पत्र के रूप में मांगती हैं।

80 फीसदी बैंक खाते व 60 फीसदी मोबाइल कनेक्शनों को जोड़ा गया

58 करोड़ बैंक खातों का सत्यापन भी किया जा चुका है

142.9 करोड़ सक्रिय मोबाइल कनेक्शनों में से 85.7 करोड़ को जोड़ा गया है

वर्चुअल आईडी का विकल्प

यूआईडीएआई ने हाल ही में हर आधार कार्ड धारक को वर्चुअल आईडी देने करने की योजना पेश की है। इससे आपको जब भी अपने आधार की जानकारी कहीं देने की जरूरत पड़ेगी, तो आपको 12 अंकों के आधार नंबर की बजाय 16 नंबर की वर्चुअल आईडी देनी होगी।

समयसीमा बढ़ाई जाए :एसोचैम

उद्योग संगठन एसोचैम ने केंद्र सरकार से मांग की है कि बैंक खातों को आधार से जोड़ने की समय-सीमा मौजूदा 31 मार्च से आगे बढ़ाई जाए क्योंकि कई फर्जीवाड़ों के मद्देनजर इस समय बैंकों के कर्मचारी उनसे निपटने के लिए अपनी प्रक्रिया को पुख्ता करने में व्यस्त हैं। एसोचैम ने कहा कि ग्राहकों पर बैंकों से ही नहीं भुगतान सेवा कंपनियों से भी दबाव बनाया जा रहा है जिससे काफी उथल-पुथल की स्थिति पैदा हो सकती है।